खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश

Pairvi

जी-30, प्रथम तल, लाजपत नगर -3, नई दिल्ली -110024
फोन : +91-11-29841266,
ईमेल : pairvidelhi1@gmail.com, pairvidelhi@rediffmail.com
वेब : www.pairvi.org

[kqnjk O;kikj esa fons’kh fuos’k

[knjk 0;kikj e fon'kh fuo'k
eb 2013

bl Ádk'ku dk y[kd vkj Ádk'kd dk gokyk nr g, xj okf.kfT;d mÌ';k d fy,
iu#Riknu fd;k tk ldrk gA

liknd % vt; dekj >k

Ádk'kd

ijoh

th&30] ÁFke ry] yktir uxj - 3] uÃ fnYyh&110024

Qku % $91&11&29841266

Ãey % pairvidelhi1@gmail.com, pairvidelhi@rediffmail.com

oC % www.pairvi.org

lg;kx

ÃDdk dkij'ku

प्रिय साथियो,

खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश का मुद्दा बड़ा ही संवेदनशील रहा है। सरकार नव–उदारवादी नीति की राह पर चल रही है, और विदेशी निवेश का बढ़ावा इसका प्रमुख हिस्सा है। देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति के मद्देनजर एफडीआई को प्रमुख समाधान के रूप में देखा जा रहा है। खुदरा व्यापार अब तक अनछुआ था, लेकिन एक ही बार में सरकार ने 51 प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति दे दी है जिससे देश के लगभग 4 करोड़ खुदरा व्यापारियों के सामने गंभीर संकट पैदा हो गया है। व्यापारियों को इससे अपने अस्तित्व पर खतरा नजर आ रहा है। उनका तर्क है कि कोई भी छोटा व्यापारी विशालकाय विदेशी कंपनियों से प्रतिस्पर्द्धा में कैसे टिक सकता है। सरकार इस असंतुलित प्रतिस्पर्द्धा को रोकने का कोई स्पष्ट उपाय नहीं सुझा रही है। हालांकि सरकार का कहना है कि इससे खुदरा व्यापार संगठित होगा और बुनियादी अधिसंरचना में भी सुधार होगा।

इस पुस्तक में इन्हीं कुछ बातों की पड़ताल करने का प्रयास किया गया है। आशा है आप अपने सुझावों से हमें जरूर अनुगृहित करेंगे।

धन्यवाद

अजय के. झा

[kqnjk O;kikj esa fons'kh fuos'k% frtkjr dh fl;klr

केन्द्र की यूपीए सरकार बहुब्रांड खुदरा व्यापार में एफडीआई की मंजूरी संसद से दिलाने में सफल रही है। कैबिनेट के इस निर्णय को संसद की मुहर 7 दिसंबर 2012 को लग गई। सरकार का मानना है कि इससे अर्थव्यवस्था में गिरावट, बढ़ती मुद्रास्फीति और विदेशी निवेश में कमी जैसी स्थितियों से निपटने में मदद मिलेगी। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों द्वारा सरकार की अर्थनीति की आलोचना भी कम हो जाएगी। एफडीआई के समर्थकों का यह दावा है कि इससे निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनेगा और देश में पूंजी निवेश बढ़ेगा जिससे सरकार की आर्थिक साख बेहतर होगी।

वित्तीय वर्ष 2012–2013 में आर्थिक विकास दर 5.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है। यह पिछले दशक की सबसे न्यूनतम वृद्धि दर है। विदेशी निवेश भी घटकर जीडीपी का 30 प्रतिशत हो गया है, जो कि 2007–08 में 36 प्रतिशत था। इस दौरान जीडीपी में विकास दर 9 प्रतिशत रहा था। प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में कोर सेक्टर प्रोजेक्ट के लिए 2 लाख करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य रखा है। सरकार का मानना है कि इन परिस्थितियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ही एक मात्र सहारा है जिसके भरोसे इस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है।

हालांकि संसद की मंजूरी मिलने के बाद भी सरकार की बाधा दूर नहीं हुई है। भारत में वॉलमार्ट को लेकर लॉबिंग करने के आरोप लगते रहे हैं। वॉलमार्ट ने लॉबिंग डिस्क्लोजर रिपोर्ट में अमेरिकी सिनेट में बताया कि वर्ष 2008 से लेकर अब तक 125 करोड़ रुपये खर्च किए गए जिसमें भारत में व्यापार के लिए अनुकूल माहौल बनाने का खर्च भी शामिल है। विपक्षी दलों का मानना है कि लॉबिंग भारत में प्रतिबंधित है और वॉलमार्ट ने गलत तरीकों से भारत में व्यापार को बढ़ाया है। घूसखोरी और लॉबिंग के बीच की विभाजन रेखा पानी पर खींची गई लकीर के समान है। इसकी जांच होनी चाहिए। सरकार ने भी मामले की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। बहरहाल वॉलमार्ट के स्थानीय संयुक्त उद्यम भारती–वॉलमार्ट के अधिकारियों ने फॉरेन करप्पट प्रेक्टिसेज एक्ट का हवाला देते अनियमितताओं से इंकार किया है।

वहीं दूसरी ओर विदेशी निवेश का विरोध करनेवाली पार्टियों और सिविल सोसाइटी का मानना है कि खुदरा व्यपार में विदेशी निवेश करोड़ों लोगों की नौकरियां छीन लेगा। उनका तर्क यह है कि सुपर मार्केट छोटी किराना दुकानों को निगल जाते हैं। अमेरिका और यूरोप में तो यह छोटी दुकानें ख़त्म हो ही चुकीं हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि एक वालमार्ट सुपर स्टोर के आस पास के लगभग 1,300 छोटी खुदरा दुकानें बंद हो जाती हैं और कम से कम 3,900 लोगों का रोजगार छिन जाता है।

सरकार ने खुदरा क्षेत्र में भी विदेशी निवेश के फैसले को कई और फैसलों के साथ जोड़ कर पेश किया है। मसलन, उड्डयन क्षेत्र में विदेशी निवेश का भी फैसला साथ में किया गया है। लेकिन उड्डयन में विदेशी निवेश खुदरा क्षेत्र में निवेश से काफी अलग है। विमान कंपनियां किसकी चल रही है, इससे देश के आम आदमी का कोई सरोकार नहीं लेकिन खुदरा व्यापार देश के सामान्य लोगों की रोजी–रोटी का वैसा ही जरिया है, जैसे कृषि। कृषि की तरह ही खुदरा व्यापार भी अकुशल और पिछड़ा हुआ है।

खुदरा व्यापार भारतीय अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख स्तंभ है। देश के सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान 14 से 15 प्रतिशत है। 45 हज़ार करोड़ रुपये के इस क्षेत्र को विदेशी कंपनियों के लिए द्वार खोलने के क्या मायने है? लगभग 1.20 करोड़ दुकानों में काम करने वाले 4 करोड़ लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या सचमुच किसानों को इससे राहत मिलेगी और बिचौलिये कम होंगें? क्या सचमुच कृषि उत्पाद कम खराब होंगे और महंगाई में कमी आएगी?

यह संभव है कि खुदरा बिक्री की विदेशी श्रृंखलाएं इस धंधे में कुशलता लाएं और सुधार भी हो। लेकिन, सवाल यह है कि वह किस कीमत पर होगा? क्या इससे करोड़ो छोटे व्यवसायी अप्रभावित रह पायेगें, क्योंकि उन पर प्रभाव पड़ने का मतलब है कि करोड़ों लोगों की रोजी रोटी पर चोट करना।

D;k g ÁR;{k fon'kh fuo'k ¼,QMhvkÃ½ ?

सामान्य शब्दों में किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाता है। ऐसे निवेश से निवेशकों को दूसरे देश की उस कंपनी के प्रबंधन में कुछ हिस्सा हासिल हो जाता है, जिसमें उसका पैसा लगा होता है। आमतौर पर माना यह जाता है कि किसी निवेश को एफडीआई का दर्जा दिलाने के लिए विदेशी निवेशक को कंपनी का कम से कम 10 प्रतिशत शेयर खरीदना पड़ता है। इसके साथ उसे निवेश वाली कंपनी में मताधिकार भी हासिल हो जाता है।

खुदरा व्यापार में 51 प्रतिशत विदेशी निवेश का अभिप्राय यह है कि निवेश करने वाली विदेशी कंपनियां भारतीय कंपनी के 51 प्रतिशत शेयर धारक हो जायेगी अर्थात् उनका उस भारतीय कंपनी पर मालिकाना हक हो जायेगा क्योंकि आधे से अधिक शेयर की मालिक विदेशी कंपनियां हो जायेगीं। इसे इस प्रकार समझा जा सकता है कि अगर अमेरिकी भीमकाय कंपनी, वॉलमार्ट भारत की भारती इंटरप्राइजेज के साथ भारतीय खुदरा व्यापार में आता है तो वॉलमार्ट भारती इंटरप्राइजेज के 51 प्रतिशत शेयर का मालिक होगा, और इसे कंपनी का मालिकाना हक भी होगा।

ÁR;{k fon'kh fuo'k d rjhd

1. विदेशी कंपनी द्वारा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक यानी सब्सिडियरी कंपनी शुरू करना – इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि वोडाफोन ग्रुप एक पब्लिक लिमीटेड कंपनी है। जिसका मुख्यालय लंदन में है। यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मोबाईल टेलीकम्यूनिकेशन कंपनी है। लेकिन इसने भारत में वोडाफोन इंडिया नाम से पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी खोली हुई है।

2. दूसरे देश में स्थित किसी संबद्ध उद्यम का शेयर खरीदना – भारत की प्रमुख गैर सरकारी बैंकिंग कंपनियों जैसे आईसीआईसीआई, एचडीएफसी आदि का 51 प्रतिशत से अधिक शेयर विदेशी कंपनियों के पास है। जो कंपनी के लिए एफडीआई का प्रमुख स्रोत हैं।

3. कंपनियों का विलय या अधिग्रहण करना – विलय में दो अलग अलग कंपनियां मिलकर एक अलग कंपनी बना लेते हैं। जैसे हांगकांग की हचिसन प्राईवेट लिमिटेड और भारत की इस्सार टेलीकॉम ने मिलकर हचिसन इस्सार कंपनी बना ली। लेकिन अधिग्रहण में विदेशी कंपनी का स्थानीय कंपनी पर अधिकार हो जाता है और स्थानीय कंपनी का अस्तित्व खत्म हो जाता है। जैसे वोडाफोन ग्रुप ने हचिसन इस्सार कंपनी का अधिग्रहण कर लिया और हचिसन इस्सार कंपनी का अस्तित्व खत्म हों गया।

4. किसी विदेशी कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम लगाना – जैसे वॉलमार्ट, भारती इंटरप्राइजेज के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में भारती–वॉलमार्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई। इसमें दोनों कंपनियों का बराबर–बराबर हिस्सा है।

Hkkjr e ,QMhvkÃ dh uhfr

सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर एक नीतिगत ढांचा तैयार किया है। जिसकी प्रत्येक वर्ष समीक्षा की जाती है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) प्रेस नोट/प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से नीतिगत घोषणा करता है जिसे विदेशी मुद्रा प्रबंधन विनियम, 2000 में संशोधन के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित किया जाता है। यह अधिसूचनाएं प्रेस नोट/प्रेस विज्ञप्ति के जारी होने की तिथि से प्रभावी होती हैं। डीआईपीपी एफडीआई नीति का नोडल विभाग होता है।

fuo'k dk Áo'k ekx

किसी भी अनिवासी भारतीय द्वारा दो विभिन्न मार्गों से निवेश किया जाता है–स्वचालित या स्वतः अनुमोदन मार्ग और सरकारी मार्ग। स्वतः अनुमोदन मार्ग के तहत अनिवासी निवेशक अथवा भारतीय कंपनी को निवेश के लिए भारत सरकार या आरबीआई से अनुमोदन की कोई जरूरत नहीं है। इसमें प्रायः शत प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति वाले सेक्टर शामिल होते हैं। सरकारी मार्ग में सरकार की पूर्वानुमति जरूरी है। इसके लिए विदेशी निवेश के प्रस्तावों पर विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) से अनुमति की जरूरत होती है।

fofHkUu lDVjk e ,QMhvkÃ dh lhek vkj Áo'k ekx

Ø- l-	{k=@xfrfof/k	,QMhvkÃ lhek	Áo'k ekx
1-	—f"k ,o i'kqikyu vFkkr i"ikRiknu] ckxckuh] e/kqeD[kh ikyu] lCth dh [krh] cht vkj jkiu lkekxh dk mRiknu] vkj lc) {k= l tqMh lok,	100%	Lopkfyr
2-	pk;ckxku	100%	ljdkjh
3-	[kuu& ghjk] lkuk] pknh vkj vU; dherh v;Ld fdLr VkbVfu;e ;qDr [kfutk vkj v;Ldk dk NkMdj	100%	Lopkfyr
4-	VkbVfu;e okyk [kfutk vkj v;Ldk dk [kuu] iFkDdj.k] vkj bldk eY; lo/ku	100%	ljdkjh
5-	iVkfy;e ,o Ák—frd xl	100%	Lopkfyr
6-	fuek.k fodkl] Vkmuf'ki vkokl] bekjrnkj ljpuk vkj vk|kfxd ikd	100%	Lopkfyr
7-	j{kk	26%	ljdkjh
8-	,;jikV ¼xhuQhYM ifj;kstuk½	100%	Lopkfyr
9-	Vyhdke lok,	74%	49% Lopkfyr] 'k"k ljdkjh
10-	udn nk eky yk ¼d'k ,.M dh½ Fkkd 0;kikj	100%	Lopkfyr
11-	flxy czkM [kqnjk 0;kikj	100%	ljdkjh
12-	chek	26%	Lopkfyr
13-	xj foRrh; dEiuh	100%	Lopkfyr
14-	Hk"kt	100%	Lopkfyr

स्रोतः डीआईपीपी सर्कुलर अप्रैल 2012

fon'kh fuo'k d rjhd

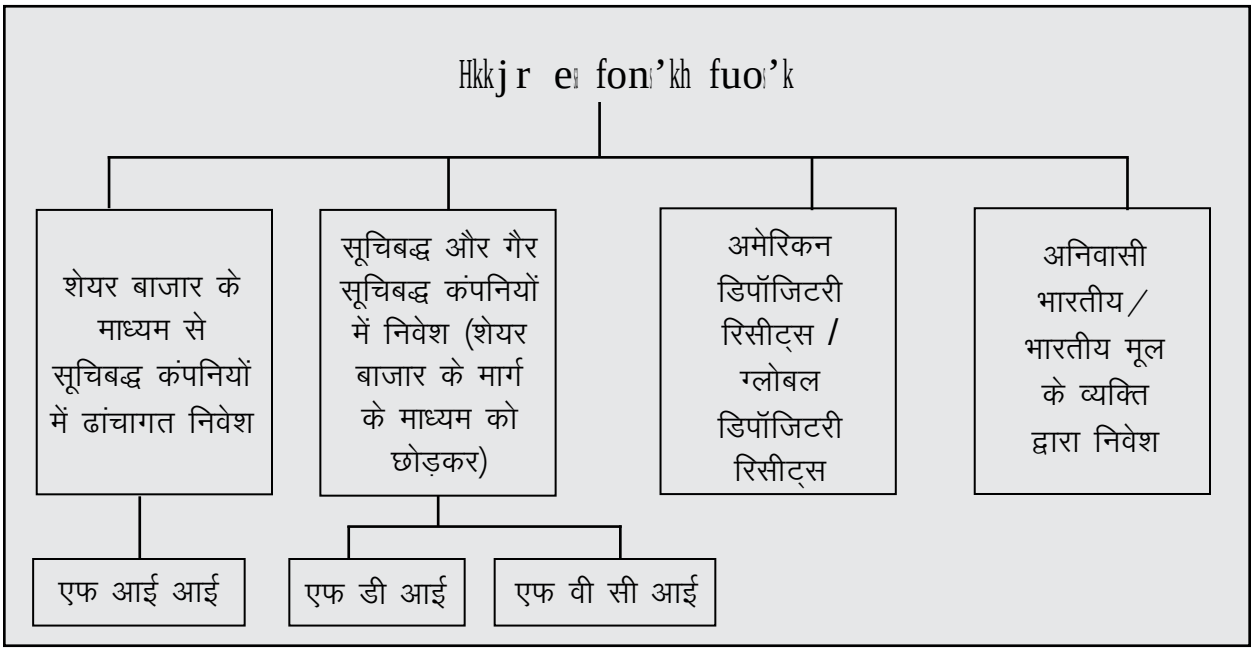

,QohlhvkÃ % "विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक" (एफवीसीआई) का अर्थ एक ऐसे निवेशक से है जो विदेश में स्थापित हो और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक) विनियमन 2000 के अनुसार उद्यम पूंजी निधि या उद्यम पूंजी उपक्रमों में निवेश प्रस्तावित करता हो। एफवीसीआई, कंपनी, ट्रस्ट या कॉर्पोरेट समूह के रूप में निवेश करता है।

सेबी नियमों के अनुसार कोई भी पंजीकृत विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक किसी भारतीय उद्यम पूंजी उपक्रम अथवा उद्यम पूंजी निधियों की ईक्विटी, ईक्विटी संबद्ध लिखतों, कर्ज, कर्ज लिखतों और डिवेंचरों में उनके प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या निजी तौर पर शेयर आवंटन के जरिए या उद्यम पूंजी निधि द्वारा स्थापित योजनाओं व निधियों की इकाईयों में निवेश कर सकती हैं।

उद्यम पूंजी वास्तव में निवेशकों द्वारा छोटे व्यवसायों या नए व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए दी जानेवाली पूंजी है। यह एक जोखिम भरा पूंजी निवेश है लेकिन इसमें संभावनाएं अपार होती हैं।

,QvkÃvkÃ% "विदेशी संस्थानिक निवेशक" (एफआईआई) का अर्थ ऐसी विदेशी संस्था से है जो भारत में निवेश का प्रस्ताव करती हो और भारतीय प्रतिभूति एंव विनिमय बार्ड (एफआईआई) के विनियमनों 1995 के अनुसार एफआईआई के रूप में पंजीकृत हो। संस्थागत निवेशक ऐसी संस्थाएं हैं जो छोटे और मंझौले निवेशकों से पैसा लेकर संगठित रूप से उनका निवेश करते हैं। इस रकम का उपयोग प्रतिभूति, रियल स्टेट और अन्य संस्थाएं जैसे बैंक, बीमा कंपनी, पेंशन, म्यूचुअल फंड आदि में निवेश के रूप में होता है। वास्तव में संस्थागत निवेशक दूसरे निवेशकों की ओर से निवेश करता है। हालांकि यह निवेश कम अवधि के लिए होता है।

fMikftVjh fjlhVl ¼Mhvkj½ % डिपॉजिटरी रिसीट्स का अर्थ एक प्राकाम्य (निगोशियबल) प्रतिभूति से है जिसे भारतीय कंपनी की ओर से किसी डिपॉजिटरी बैंक द्वारा देश से बाहर जारी किया जाता है। डी आर का लेन देन स्टॉक एक्सचेंज पर अमेरिका, सिंगापुर

लक्समबर्ग आदि में किया जाता है। जो डी आर अमेरिकी बाजारों में सूचिबद्ध है उसे अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स (एडीआर) और जो अन्यत्र व्यापार हेतु सूचिबद्ध है उसे ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स (जीडीआर) के रूप में जाना जाता है।

ikVQkfy;k fuos'k

इसमें निवेशक दूसरे देश में शेयर या बॉण्ड के माध्यम से निवेश करता है। यह तात्कालिक आर्थिक लाभ के उद्देश्य से किया गया निवेश है। पोर्टफोलियो निवेश की स्कीम के अंतर्गत किसी भारतीय कंपनी की पूंजी में कोई विदेशी संस्थानिक निवेशक (एफआईआई) निवेश कर सकती है जिसमें एफआईआई की निजी धारिता की सीमा कंपनी की पूंजी से अधिक नहीं रखी गई है। एफआईआई निवेश के लिए समग्र सीमा कंपनी की पूंजी के 24 प्रतिशत से अधिक नहीं रखा गया है।

राजनीतिक हलकों में अभी तक विदेशी निवेश की आलोचना इस बात को लेकर होती रही है कि विदेशी पूंजी निवेश बहुत थोड़े समय के लिए मुनाफा कमाने आती है। देश में उनके निवेश का दीर्घकालिक लक्ष्य नहीं होता है। गौरतलब है कि पोर्टफोलियो निवेश शेयर या बांड बाजार में आता है जबकि एफडीआई दीर्घकालिक उद्देश्यों के साथ सीधे कंपनियों या परियोजनाओं में लगाया जाता है।

Hkkjr esa [kqnjk O;kikj dh fLFkfr

खुदरा व्यापार भारत में करोड़ों लोगों के लिए आजीविका का एकमात्र और अंतिम साधन है। इसलिए यह आवश्यक है कि भारत में इसकी संरचना को समझें। भारत का खुदरा व्यापार मूलतः असंगठित है। इसमें छोटे किराना, पान बीड़ी और रेहड़ी पटरी वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। देश में लगभग सवा करोड़ खुदरा दुकानें हैं जिससे करीब 4 करोड़ लोगों को रोज़गार मिला हुआ है। अगर इनमें से हर व्यक्ति के परिवार को औसतन 4 से 5 लोगों का माना जाए तो करीब 20 करोड़ लोगों को दो वक्त की रोटी इसी खुदरा व्यापार से मिलती है। छोटी खुदरा दुकानों के घनत्व के मामलों में भारत दुनिया में अव्वल है, और यहाँ प्रति हज़ार व्यक्ति की आबादी पर 11 छोटी दुकानें हैं।

जिन लोगों को कहीं भी रोजगार नहीं मिलता, किराना दुकान उनके लिए आखिरी सहारा होता है। अवसरों के आभाव के कारण छोटी दुकान खोलना किसी व्यक्ति का स्वाभाविक निर्णय बन जाता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारत में कोई व्यक्ति अपनी रुचि के बजाए मजबूरी में छोटी दुकान खोलता है। आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ मोहन गुरूस्वामी का मानना है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में लोगों को स्वरोज़गार की आज़ादी और कम पूंजी व बुनियादी ढांचे के आभाव के कारण खुदरा व्यापार अर्थ व्यवस्था की एक मज़बूत कड़ी बन गई है, और लोगों को सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान करता है।

आई.सी.आर.आई.ई.आर (इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च इन इंटरनेशनल इकोनोमिक रिलेशंस) ने अनुमान लगाया है कि भारत का रिटेल सेक्टर 4 लाख 96 हज़ार करोड़ का है। हालांकि, भारत में संगठित खुदरा व्यापार अन्य देशों की अपेक्षा अभी शैशव काल में है। इसे निम्नलिखित आरेख से समझा जा सकता है

,QMhvkÃ ij ljdkj dk fu.k;

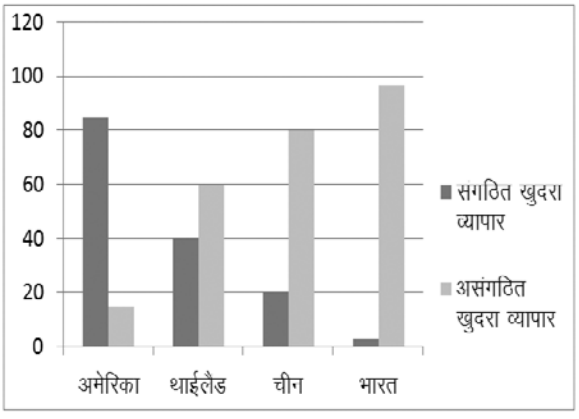

Hkkjr e fuo'k dju oky nfu;k d 10 lcl cM n'k
¼foRrh; o"k vily 2000 l ekp 2011 rd½

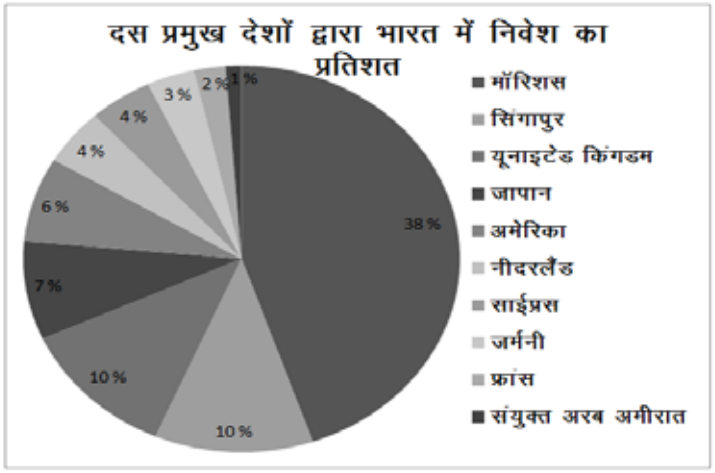

स्रोत : डीआईपीपी वार्षिक प्रतिवेदन 2011

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने खुदरा व्यापार के क्षेत्र में विदेशी निवेश का निर्णय लिया। इसके प्रमुख तथ्य इस प्रकार है –

❖ बहुब्रांड खुदरा व्यापार में 51 प्रतिशत विदेशी निवेश सरकारी मार्ग से होगा।

❖ फल सहित ताजा कृषि उत्पाद, सब्जी, फूल, अनाज, दाल, अंडे, मछली और मांस बिना ब्रेंड के हांगे।

❖ बहुब्रॉड सेक्टर में उतरने की योजना बना रही विदेशी खुदरा कंपनियों को कम से कम 10 करोड़ डॉलर का निवेश करना होगा।

❖ नियमों के तहत एफडीआई के शुरुआत के तीन साल में ही कुल निवेश का 50 प्रतिशत सहायक बुनियादी ढांचे में निवेश करना होगा। इसमें प्रसंस्करण, उत्पादन, वितरण, डिजाइन सुधार, गुणवत्ता नियंत्रण, पैकेजिंग, भंडारण, बेयर हाउस जैसे बुनियादी ढांचे शामिल हैं।

❖ कंपनियों को अपने 30 प्रतिशत उत्पाद लघु एंव मंझौले उद्योगों से लेने होंगे। केवल 10 लाख से अधिक आबादी वाले 53 शहरों में ही मेगा स्टोर खोलने की अनुमति होगी। जिन राज्यों में 10 लाख आबादी वाला एक भी शहर न हो वहां एफडीआई लागू करने का निर्णय राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया है।

हालांकि केंद्र सरकार की यह नीति राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसे लागू करने के लिए स्वतंत्र हैं। जिन राज्यों को भविष्य में इसे लागू करना होगा वह डीआईपीपी से सहमति के बाद अपने प्रदेश में लागू कर सकता है। अभी तक आंध्र प्रदेश, आसाम, दिल्ली, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान, उत्तराखंड, दमन दीउ और दादर नागर हवेली ने इसे लागू कर दिया है।
यहां यह बताना उचित होगा कि भारत की सरकार पिछले 15 वर्षों से इस दिशा में प्रयास कर रही है।

वर्ष 2002 में एन.के. सिंह कमेटी का गठन एफडीआई के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए किया गया था। योजना आयोग ने अगस्त 2001 में एन.के. सिंह की अध्यक्षता में बारह सदस्यीय एक संचालन समिति का गठन किया था। इस समिति में केंद्र एवं राज्य सरकारों के अलावा उद्योग संघों से भी सदस्य चुने गये थे। इसका उद्देश्य सरकार को निजी निवेश आकर्षित करने के लिए नीतिगत सुधार का सुझाव देना और ऐसे कारकों का पता लगाना था जो निवेश को प्रभावित करते हैं। हालांकि इस कमेटी ने एफडीआई पर प्रतिबंध को लागू रखने का सुझाव दिया था, जिसके बाद दसवीं पंचवर्षीय योजना में इस प्रस्ताव को शामिल नहीं किया गया था। इसके बाद वर्ष 2009 में वाणिज्य से संबंधित संसदीय समिति ने भी एफडीआई पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। विभिन्न साझीदारों और पहलुओं पर विमर्स के बाद संसदीय समिति ने यह सुझाव दिया था कि खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

xkj ¼tujy ,Vh vok;Ml ,DV½

इसका उद्देश्य प्राथमिक रूप से ऐसी आर्थिक लेन देन या व्यवस्था को रोकना है जो मुख्यतः कर लाभ के उद्देश्य से किया जाता है। तत्कालीन वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने मार्च 2012 में इसे लागू किया था। वास्तव में इसका उद्देश्य ऐसे निवेश और उद्यमों को रोकना है जो मॉरिशस जैसे देश में अपनी सहायक कंपनी खोलते हैं और फिर भारत में निवेश करते हैं। जिससे उन्हें कर बचाने में मदद मिलती है। ऐसी कंपनियां मॉरिशस में कोई निवेश नहीं करती और सीधे भारत में पैसा लगाती हैं। डीआईपीपी के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2011 में मॉरिशस से 55 बिलियन डॉलर का एफडीआई इक्विटी भारत में आया जो कि कुल एफडीआई का 42 प्रतिशत था।

ऐसा आरोप लगाया जाता है कि भारत सहित अन्य देशों का काला धन मॉरिशस के रास्ते भारत में निवेश किया जाता है। एक अमेरिकी संस्था ग्लोबल फिनांशियल इंटिग्रिटी ने अनुमान लगाया है कि वर्ष 1948 से 2008 के बीच लगभग 462 बिलियन डॉलर का काला धन भारत से बाहर गया है। यह जीडीपी के 40 प्रतिशत के आस पास है। काले धन का मॉरिशस के रास्ते भारत में निवेश किया जाता है।

गौरतलब है कि भारत और मॉरिशस के बीच दोहरे कराधान से बचने के लिए समझौता है जिससे कंपनियों को एक आय पर एक ही देश में टैक्स लगता है, दोनों देशों में नहीं। इस टैक्स कानून से विदेशी निवेशकों को गलत तरीके से निवेश करने पर अंकुश लगाया जा सकता है। हालांकि विदेशी निवेशकों के विरोध के कारण यह कानून अभी ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। श्री मुखर्जी के राष्ट्रपति बनने के बाद प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने श्री पार्थसारथी शोम की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की थी जिसे गार

के लागू करने पर सुझाव देना था। कमेटी ने सुझाव दिया कि इसे आज के आर्थिक हालात के मद्देनजर कम से कम 3 वर्षों तक लागू नहीं करना चाहिए।

,QMhvkÃ d leFkdk vkj fojkf/k;k dk i{k

rF;	leFkdk dk nkok	fojkf/k;k dk rdl
किसानों पर प्रभाव	किसानों को सीधा फायदा होगा। विदेशी कंपनियां सीधे किसानों से कृषि उत्पाद खरीदेंगी और किसानों को अधिक मूल्य मिलेंगे।	किसानों को कोई फायदा नहीं होगा। ऐसी कंपनियां पहले ज्यादा कीमत देकर किसानों को स्थायी उपभोक्ता बनाती हैं और फिर औने पौने दाम में किसानों से उत्पाद खरीदती है।
बिचौलियों से छुटकारा	एफडीआई आने से बिचौलिए खत्म हो जाएंगे और ग्राहकों को फायदा होगा।	बिचौलिए पहले से भी ज्यादा असंगठित और व्यवस्थित हो जाएंगे और क्वालिटी कंट्रोलर, स्टैंडर्डाइजर, सर्टिफिकेशन एजेंसी और पैकेजिंग कंसलटेंट के रूप में नए बिचौलिए सामने आएंगें।
उपभेगता वस्तुओं के दाम	इससे दाम में कमी आएगी।	दाम में कोई कमी नहीं आएगी क्योंकि बड़ी खुदरा दुकानें बाजार पर धीरे धीरे एकाधिकार (मोनोपॉली) बना लेती है और बाद में यही कंपनियां मनमानी दरों पर अपने उत्पाद बेचती हैं
रिटेल व्यापार पर प्रभाव	स्वस्थ्य प्रतिस्पर्द्धा और निवेश से खुदरा व्यापार संगठित और व्यावस्थित हो जाएगा।	विदेशी कंपनियों के आने से खुदरा दुकानों के अस्तित्व पर संकट आ जाएगा। छोटी दुकानें उनके सामने प्रतिस्पर्द्धा में टिक नहीं पायेगीं और धीरे–धीरे उजड़ जायेगीं।
रोजगार	विदेशी कंपनियों के आने से रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे	अकेले वॉलमार्ट का टर्नओवर भारत के कुल खुदरा अर्थव्यवस्था के आस पास है। जिसमें 21 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है। अब अगर इतने लोगों के दम पर वॉलमार्ट उतना ही कारोबार करता है जितना कि भारत का कुल खुदरा व्यापार है, तो फिर 4–5 करोड़ लोगों के रोजगार की उम्मीद कैसे की जा सकती है?
खाद्यान्न का भंडारण	सरकार का तर्क है कि 30–40 प्रतिशत फल और सब्जी और 10 प्रतिशत अनाज समुचित भंडारण नहीं होने के कारण सड़ जाते हैं। विदेशी कंपनियों के आने से खाद्यान्न का भंडारण और अधिक सुचारू और वैज्ञानिक ढंग से होगा, जिससे अनाज को सड़ने से बचाया जा सकेगा।	सरकार भंडारण के क्षेत्र में एफडीआई की अनुमति पहले ही दे चुकी है। कोल्ड स्टोरेज के लिए 100 प्रतिशत विदेशी निवेश पहले से ही लागू हो चुका है लेकिन अब तक इस क्षेत्र में कोई भी विदेशी निवेश नहीं हुआ है। हम यह कैसे मान ले कि विदेशी कंपनियां अनाज को सड़ने से बचाने के लिए प्रयाप्त इंतेजाम करेंगी। साथ ही विरोधियों का तर्क है कि रिटेल कंपनियां विनिर्मित वस्तुओं का व्यापार ज्यादा और खराब होने वाली वस्तुएं जैसे फल, सब्जी का कम करती हैं।
मुद्रास्फीति	अनाज और सब्जियों के दाम कम होने से मुद्रास्फीति में कमी आएगी।	मुद्रास्फीति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक की खरीदगी और वितरण की व्यवस्था व्यापक नहीं कर ली जाए।
बुनियादी ढांचा	इससे बुनियादी ढांचे में सुधार होगा क्योंकि कंपनियां अपने कुल निवेश का 50 प्रतिशत बैकएंड बुनियादी ढांचे में लगाएगी।	विदेशी कंपनियां सिर्फ मुनाफे के लिए आती हैं न की व्यवस्था सुधारने के लिए।

fo'k"kKk dh jk;

1. कृषि विशेषज्ञ डॉ. देविंदर शर्मा के मुताबिक खुदरा बाजार में विदेशी निवेश के सबसे बड़े पैरोकार अमेरिका में भी खुदरा बाजार में विदेशी निवेश किसानों और कृषि के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ है। अमेरिका में फेडरल सरकार की मदद की वजह से वहाँ के किसान फायदे में रहते है। 2008 में आए फार्म बिल में अमेरिका ने अगले पाँच सालों के लिए कृषि क्षेत्र के लिए 307 अरब डॉलर का प्रावधान किया गया था। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर खुदरा में एफडीआई या बड़ी पूंजी लगाने

से किसानों को बड़ा फायदा होता तो, अमेरिकी सरकार को अपने किसानों को भारी भरकम सब्सिडी क्यों देनी पड़ती? पश्चिमी देशों में किसानों को कई तरह की सब्सिडी मिलने के बावजूद यह बात सामने आई है कि यूरोप में किसान तेज़ी से खेती बाड़ी का काम छोड़ रहा है। जो लोग यह समझते हैं कि एफडीआई आने के बाद किसानों की स्थिति बेहतर होगी उन्हें यह समझने की जरूरत है कि किसानों की मूल समस्या पूंजी का अभाव और अधिसंरचना की कमी है, और खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश इसे खत्म नहीं कर सकती। यहीं नहीं, अगर सबसे बड़ी रिटेल कंपनियों से किसानों की आय बढ़ती है तो भारत में रिलांयस से लेकर आदित्य बिड़ला समूह जैसे दर्जनों कंपनियों की मौजूदगी का फायदा किसानों को मिलना चाहिए।

2. नोवेल पुरस्कार प्राप्त प्रख्यात अर्थशास्त्री प्रोफेसर जोसफ एसटिग्लिट्ज के अनुसार विदेशी निवेश के लिए द्वार खोलना भयावह परिणति को आमंत्रित करना है। इससे आर्थिक अस्थिरता पैदा होगी। उदारीकरण के इस दौर में विनियमित पूंजी और वित्तीय बाजार आर्थिक अस्थिरता पैदा करती है। यह अस्थिरता वृद्धि के लिए भी अवरोधक है और गरीबों के लिए भी। इन्होंने खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश को गलत कहा है। इनका कहना है कि विदेशी निवेशकों पर हम क्यों भरोसा करें खासकर जब वालमार्ट जैसी कंपनियां श्रमिक विरोधी गतिविधि के लिए विख्यात हैं।

3. प्रोफेसर पुष्पेश पंत के अनुसार खुदरा व्यापार को बड़ी कंपनियों के हवाले करना समसामायिक भारतीय हालात में तर्क संगत नहीं लगता। यह जरूरी नहीं कि थोक के भाव माल खरीदने वाला इसे अधिक मुनाफे का लालच छोड़ पहले से कम कीमत पर ग्राहक या उपभोक्ता तक पहुंचाएगा। यह सोचना भी नादानी होगी कि किसी भी पूंजीपति या उद्यमी का परोपकारी मकसद किसी विकासशील देश के आधारभूत ढांचे में सुधार लाकर परिष्कृत तकनीक का प्रसार होता है। कुछ समय के लिए भले ही कुछ लोगों को अस्थाई रोजगार मिल सकता है, एक बार बाजार में अपना एकाधिकार स्थापित करने के बाद उनके लिए सिर्फ यह महत्वपूर्ण रहता है कि कारोबार लाभप्रद है या नहीं।

4. न्यायमूर्ति राजिंदर सच्चर कहते हैं कि आखिर किस तर्क से सरकार यह कहती है कि भारत में इसका असर उलटा होगा? वॉलमार्ट जो कुछ बेचती है उसका 92 प्रतिशत चीनी कंपनियों से आता है। भारत का बाजार पहले ही चीन के सस्ते माल से पटा पड़ा है। ऐसे में भारत सरकार पूरी ईमानदारी से बताए कि क्या वह अब भी विदेशी उद्यमों के लिए खुदरा बाजार खोलकर देश के करोड़ों लोगों की रोजी–रोटी छीनने को तैयार है?

5. भारतीय किसान यूनियन के महासचिव श्री युद्धवीर सिंह का कहना है कि हम 80 के दशक में पेप्सिको

के कड़वे अनुभव को भूले नहीं हैं जब किसानों ने कंपनियों के सभी निर्देशों का पालन करते हुए बीज और उर्वरक खरीदे। उनके निर्देशों के अनुसार फसल लगाई। लेकिन, उत्पाद खरीदते समय ग्रेडिंग स्कीम लाकर ज्यादातर माल खरीदा ही नहीं। पेप्सिको पंजाब ने बागवानी क्रांति लाने का दावा किया था। इसकी क्या गारंटी है कि वॉलमार्ट ऐसा नहीं करेगा।

सरकार वॉलमार्ट के सस्ते आयात से सामान खरीद कर भारत में डंप करने से कैसे रोक पाएगा।

6. यूएफसीबी (यूनाइटेड फुड एंड कॉर्मशियल वर्कस यूनियन) के एसोसिएट रिसर्च डाइरेक्टर इयान कैम्पबेल के अनुसार अनेक दशों में वॉलमार्ट की गतिविधि संदिग्ध है। वॉलमार्ट के कानूनी सलाहकारों ने खुद स्वीकार किया है कि न सिर्फ मैक्सिकों बल्कि ब्राजील, चीन, दक्षिण अफ्रीका और भारत में भी कंपनी ने अपनी भ्रष्ट्राचार विरोधी नीतियों पर पुनर्विचार का सुझाव दिया है। स्वीटजरलैंड स्थित विश्वस्तरीय व्यापार संघ, यूएनआई ग्लोबल यूनियन ने भारत सरकार के औद्योगित नीति और संवर्धन विभाग को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। जिसमें यूनियन ने वालमार्ट के मूल्य निर्धारण, सोर्सिंग और श्रम विरोधी नीतियों का हवाला देते हुए भारत में खुदरा व्यापार में निवेश पर चिंता व्यक्त की थी। उसपर अपने प्रतियोगियों को प्रतियोगिता से बाहर करने के लिए अनुचित तौर–तरीके अपनाने के आरोप भी लगाते हैं।

okyekV d vkx dku fVd- xk\

वॉलमर्ट भारतीय बाजार में घुसने के लिए बेताब है। देश में भी अर्थव्यवस्था के मैनेजरों से लेकर अमीरों और मध्यवर्ग का एक हिस्सा वॉलमार्ट के लिए पलक–पावड़े बिछाये हुए है। आखिर वॉलमार्ट कोई मामूली कंपनी नहीं है। यह दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर कंमपनियों की वर्ष 2012 की फार्च्युन– 500 सूची में दूसरे नंबर की कंपनी है।

इससे पहले वह लगातार दो वर्षों तक पहले नंबर पर थी। उन वर्षों 2011 में कुल 447 अरब डालर का कारोबार किया। हालांकि उसके मुनाफे में मामूली

okyekV vxj n'k gkrk rk ;g nfu;k dh 25 oh cMh vFk0;oLFkk gkrh

गिरावट दर्ज की गई है। इसके बावजूद उसका कुल मुनाफा 15.7 अरब डालर का रहा। इसकी कुल परिसंपत्तियां 193.4 अरब डालर की हैं जबकि शेयर बाजार में उसकी कीमत 71.3 अरब डालर हैं। अलग–अलग नामों से दुनिया के 15 देशों में उसके लगभग 8970 सुपर स्टोर्स हैं और लगभग

21–22 लाख कर्मचारी/अधिकारी काम करते हैं। हर सप्ताह उसके स्टोर्स में दस करोड़ उपभोक्ता पहुंचते हैं। भारत में वह थोक व्यापार (कैश एंड कैरी) में भारती के साथ सयुंक्त उपक्रम में 'बेस्ट प्राइस' नाम से स्टोर्स चलाती हैं।

अपने विशाल आकार और कारोबार के कारण वॉलमार्ट के आगे भारत के छोटे दुकानदारों के टिकने की बात तो दूर है। देश के सबसे बड़े कारपोरेट समूहों के लिए भी उससे प्रतियोगिता करना मुश्किल होगा, देश की दस सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनियों का मुनाफा भी वालमार्ट के मुनाफे से कम है। ऐसे में कितनी देशी कंपनियां उससे मुकाबले में टिक पायेंगी?

वॉलमार्ट का राजनीतिक रसूख भी बहुत ज्यादा है। यहां तक कि अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन वालमार्ट के 'बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर' में रह चुकीं हैं।

nfu;k d nl j n'kk e [knjk 0;kikj e ÁR;{k fon'kh fuo'k dh uhfr

चीन, थाइलैंड, रूस, इंडोनेशिया, ब्राजील, अर्जेंटीना, सिंगापुर, चिली जैसे देशों में खुदरा व्यापार में शत–प्रतिशत एफडीआई लागू है। भारत में चीन के मॉडल का उदाहरण दिया जाता है, लेकिन चीन में 12 वर्ष के लंबे अंतराल में शत–प्रतिशत लागू किया गया। वर्ष 1992 में चीन ने 26 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी थी और उसके 10 वर्ष बाद 49 प्रतिशत एफडीआई लागू किया गया। विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता मिलने के बाद दिसंबर 2004 में एफडीआई की सीमा खत्म कर दी गई। वॉलमार्ट 1996 में चीन में पहली बार अपना स्टोर खोला और आज उसके 350 से अधिक स्टोर खुल चुके हैं। लेकिन प्रारंभ में बिजिंग, शंघाई और शेंचेन जैसे महानगरों में ही रिटेल स्टोर खोलने की इजाजत थी। बाद में वैसे छोटे शहरों में वॉलमार्ट स्टोर खोले गए जहां स्थानीय प्रतिस्पर्द्धी नगण्य थे। इस प्रकार स्पष्ट है कि चीन ने अपने स्थानीय रिटेलरों के हितों की रक्षा की । हम चीन से भारत की रिटेल नीति की तुलना कर रहे हैं। लेकिन क्या हम चीन की तरह स्थानीय विक्रेताओं की रक्षा कर पाएंगे, खासकर जब हमारे पास ऐसे प्रतिस्पर्द्धा को रोने का कोई व्यवस्थित तंत्र मौजूद नहीं है।

यही नहीं, दुनिया के कई देशों के अनुभव भी खासे कड़वे हैं। थाईलैंड में बड़े रिटेल स्टोर्स में कीमतें छोटे खुदरा व्यापारियों की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक पायी गईं जबकि अर्जेंटीना में पूरे 90 के दशक में कीमतों में यह अंतर 14 प्रतिशत अधिक था। वियतनाम में 2002 में बड़े रिटेल स्टोर्स में कीमतें 10 प्रतिशत अधिक थीं। मेक्सिकों में भी यही हाल है जबकि खुद अमेरिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुपर स्टोर्स ने 1994 से 2004 के बीच टमाटरों की कीमतें 46 प्रतिशत बढ़ा दीं लेकिन किसानों को मिलने वाली वास्तविक कीमत में 25 प्रतिशत की कमी आ गई। असल में यह समझना बहुत जरूरी हैं कि वैश्विक स्तर पर कृषि उत्पादों के व्यापार और वितरण पर बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों जैसे कारगिल, कांटिनेंटल और लुइ ड्रेफस और वॉलमार्ट, टेस्को, मेट्रो आदि का कब्जा है। उदाहरण के लिए ब्राजील में बड़े रिटेल स्टोर्स के खुलने के बाद 1987 से 1996 के बीच की फल–सब्जियों की बिक्री में छोटे खुदरा दुकानदारों की हिस्सेदारी में 28 प्रतिशत की

गिरावट दर्ज की गई जबकि दूध की बिक्री में छोटे स्टोर्स और दूधियों के हिस्से में क्रमशः 27 और 53 प्रतिशत की कमी आई।

इसी तरह अर्जेंटीना में 1984 से 1993 के बीच बड़े रिटेल के आने के बाद छोटे दुकानदारों की संख्या में कोई 30 प्रतिशत और खुदरा व्यापार में रोजगार पाए लोगों की संख्या में 26 प्रतिशत की गिरावट देखी गईं। आज लातिन अमेरिका में खाद्य वस्तुओं के खुदरा व्यापार का 60 प्रतिशत से ज्यादा बड़े और संगठित रिटेल स्टोर्स के हाथों में है। इंडोनेशिया में सिर्फ एक साल (2002–03) में 1.54 लाख यानी 9 प्रतिशत छोटी दुकानें बंद हो गईं। ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है। भारत जैसे देश के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण कसौटी है क्योंकि यहाँ खुदरा व्यापार रोजगार की दृष्टि से कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण क्षेत्र है।

okyekVZ ij Hkkjr esa ,QMhvkÃ fu;eksa ds mYya?ku dk vkjksi

वैज्ञानिक एवं पर्यावरणविद वंदना शिवा ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर भारती वॉलमार्ट प्राइवेट लिमिटेड पर एफडीआई नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। याचिका में कहा गया है कि भारती वॉलमार्ट कंपनी देश में मल्टी ब्रांडों की बिक्री कैश एंड कैरी ट्रेड के माध्यम से कर रही है। जबकि इसे देश में केवल चुनिंदा वस्तुओं का थोक व्यापार करने की ही अनुमति है। विदेशी कंपनियां भारतीय कंपनियों के नाम का इस्तेमाल कर उन्हें निवेश का लाभ देकर देश में अन्य व्यवसायों को प्रभावित कर रही हैं। ऐसा करके वह एफडीआई के नियमों का उल्लंघन कर रही हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए के सीकरी और न्यायमूर्ति अनिल कुमार की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, भारती वॉलमार्ट प्राइवेट लिमिटेड और भारती रिटेल लिमिटेड को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

गौरतलब है कि विरोधों के बावजूद वॉलमार्ट वर्ष 2007 से ही भारती रिटेल लिमिटेड कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम लगाकर भारतीय खुदरा व्यापर के पिछले दरवाजे से पहुंच चुकी है। इजी डे और वेस्ट प्राइस के नाम से इनकी दुकाने चलती हैं, हालांकि यह अनुमति थोक व्यापार के लिए थी। नई परिस्थितियों में जब खुदरा व्यापार में भी एफडीआई की अनुमति मिल गई है, सरकार इस आरोप को निराधार बताती है।

रिटेल क्षेत्र में विदेशी निवेश अन्य क्षेत्रों के निवेश से भिन्न है। इसका सीधा संबंध छोटे विक्रेताओं और किसानों से है। इसलिए विदेशी कंपनियों का विस्तार इस क्षेत्र में बड़ी ही सावधानी से करना चाहिए। चीन, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया जैसे देशों में इसका प्रयोग हुआ है। लेकिन इन देशों ने संतुलित दृष्टिकोण अपनाया और चरणबद्ध तरीकों से विदेशी कंपनियों के लिए द्वार खोले। जैसा कि स्पष्ट है कि हमने पहली ही बार में 51 प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति दी है जो कि आधे से अधिक है। हमें ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि बड़ी कंपनियों का छोटे फुटकर विक्रेताओं के साथ घातक प्रतिस्पर्द्धा नहीं हो। हमारे पास इसके लिए विशिष्ट तंत्र होनी चाहिए। राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग की तरह एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो केवल विदेशी कंपनियों और भारत के खुदरा व्यापारियों के बीच की प्रतिस्पर्द्धा पर नजर रखे।

सरकार कहती है कि यह पहल भारतीय खुदरा व्यापार को और संगठित करेगी। लेकिन इसके लिए यह जरूरी है कि स्वस्थ्य प्रतिस्पर्द्धा हो। विशेषज्ञों की राय है कि भारत को संतुलित तरीके से चरणबद्ध रूप में इसका विस्तार करना चाहिए। साथ ही ऐसे नियम स्थापित करने होंगे जिससे खुदरा व्यापार और व्यापारियों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। जिससे किसानों और विक्रेताओं के हितों की रक्षा हो सके। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि सरकार छोटे उत्पादक और पारंपरिक खाद्य विक्रेताओं को सहायता प्रदान करे।

lnHkZ lwph

1- ih,e lsV~l #ih t VªsykjZ dk djksM+ bUÝk bUoLVeSUV VkxsZV Qkj 9 ijlsUV xzksFk - n bafM;u ,DlÁsl- uÃ fnYyh 6 twu 2012- http://www.indianexpress.com/news/pm-sets-rs-2- lakh-cr-infra-investment-target-for-9-growth/958657/

2- MhvkÃihih- fMLd'ku isij- 27 tqykÃ 2010- http://dipp.gov.in/English/Discuss_paper/Re ponses34_RetailTrading_27July2010.pdf

3- fjVsfyax bu bafM;k- fofdihfM;k- http://en.wikipedia.org/wiki/Retailing_in_India

4- IySuV fjVsy- http://www.planetretail.net

5- ,QMhvkÃ bu fjVsy% le vuvkulMZ Dos'kpu- Mkmu Vw vFkZ] 6 fnlEcj 2011- http://www.downtoearth.org.in/content/fdi-retail-some-unanswered-questions

6- MhvkÃihih- okf"kZd Áfrosnu 2011- http://www.dipp.gov.in/English/Publications/SIA_NewsLetter/AnnualReport2011/Chapter1.4.A.iii.pdf

7- bdksukWfed ,.M ikWfyfVdy ohdyh & 17 fnlEcj 2011

8- ,QMhvkÃ bu fjVsfyax% ekWj cSM nSu xqM] ekbgu xq:Lokeh & 20 fnlEcj 2004

9- rhljk jkLrk- vkuUn Á/kku- http://teesraraasta.blogspot.in/

10- fVªiy Økbfll- t;rh ?kks"k- http://www.triplecrisis.com/

11- xkmuM fj;fyVh- nsfoanj 'kekZ- http://devinder-sharma.blogspot.in/

12- eSM bu ;wukbÃVsM LVsV- n fgUnw-] uÃ fnYyh- 15 flrEcj 2012- http://www.thehindu.com/opinion/op-ed/made-in-the-united-states/article3897906.ece

13- fjVsy ,QMhvkÃ feFk- Mkmu Vw vFkZ- 31 fnlEcj 2011- http://www.downtoearth.org.in/content/retail-fdi-myths

14- yhQ¶ysV ikVhZ uksV- http://www.cpim.org/documents/2011-Dec-FDI-Retail.pdf

15- vkjchvkÃ ldZqyj- 19 ekpZ 2012 . http://www.rbi.org.in/hindi/Scripts/apdir.aspx?id=3299

16- tkfu, ,QMhvkÃ fjVsy ds nl uQk uqdlku- nSfud HkkLdj-dkWe-20 flrEcj 2012- http://www.bhaskar.com/article/NAT-pros-and-cons-of-fdi-in-retail-3809347-NOR.html?seq=1

17- ,lih iztj ;wih, gkmi] ,ykbu fon